DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

06 जनवरी 2023

न्यायपालिका में लैंगिक असमानता

सन्दर्भ

सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान न्यायाधीश ने महिलाओं के "बहुत कम" प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हुए उल्लेख किया कि न्यायपालिका में लैंगिक असमानता विद्यमान है।

प्रमुख बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित अपने विदाई समारोह में , न्यायमूर्ति नज़ीर ने कहा, "सुधार और परिवर्तन के लिए हमेशा जगह होती है। उदाहरण के लिए, अगर मैं यह कहूं कि भारतीय न्यायपालिका हमारे समाज के भीतर मौजूद लैंगिक असमानता से मुक्त है, तो यह वास्तविकता से काफी दूर है ।
- ध्यातव्य है कि न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है।

भारतीय न्यायिक प्रणाली में महिलाओं की स्थिति क्या है?

- 2022 में सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग 33 न्यायाधीशों में से चार महिला न्यायाधीश थीं। यह मात्र 12% का प्रतिनिधित्व करता है।
- उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या 11.5% है।
- 1.7 मिलियन अधिवक्ताओं में से केवल 15% महिलाएँ हैं।
- राज्य बार काउंसिलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों में केवल 2% महिलाएं हैं।
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कोई महिला सदस्य नहीं है।

भारतीय न्यायिक प्रणाली में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का क्या कारण है?

- क्लाइंट पुरुष अधिवक्ताओं को वरीयता देते हैं ।
- न्यायालय कक्षों के भीतर असुविधाजनक वातावरण।
- बुनियादी ढांचे की कमी, भीड़भाड़ वाले अदालत कक्ष, महिलाओं के लिए शौचालय की कमी आदि।
- सर्वेक्षण में पाया गया कि 6,000 ट्रायल कोर्ट में से लगभग 22% में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है।

हमें महिला न्यायाधीशों की आवश्यकता क्यों है?

- महिला न्यायाधीशों ने न्याय की उपस्थिति में सुधार करने की तुलना में कहीं अधिक योगदान दिया है, उनका निर्णय न्याय की गुणवत्ता पर भी प्रभाव डालता है।
- महिला न्यायाधीशों के द्वारा जीवंत अनुभवों को न्यायिक कार्रवाइयों में प्रयोग किया जाता है जो अधिक सहानुभूतिपूर्ण और व्यापक परिप्रेक्ष्य की ओर प्रवृत्त होते हैं।
- लैंगिक रूढ़िवादिता जैसे कानूनों का पुरुषों और महिलाओं पर अलग प्रभाव को महिला न्यायाधीशों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है जिससे लैंगिक परिप्रेक्ष्य न्यायनिर्णय की निष्पक्षता में वृद्धि होती है।

लैंगिक समानता और लैंगिक समता में क्या अंतर है?

- लैंगिक समानता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के अधिकार, उत्तरदायित्व और अवसर जन्म के समय दिए गए लिंग से निर्धारित नहीं होंगे।
- · जबकि लैंगिक समता , समान व्यवहार या उपचार है जिसे अधिकारों, लाभों, दायित्वों और अवसरों के मामले में समकक्ष माना जा सकता है

प्रधान मंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) योजना

प्रसंग

हाल ही में, अधिकारियों ने कहा कि 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले कुल 165,382 स्कूलों ने अब तक प्रधान मंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) योजना के तहत उन्नयन के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ आवेदन किया है।

प्रमुख बिंदु :-

चयन के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों की अधिकतम संख्या निम्न राज्यों से है-उत्तर प्रदेश (37,065), राजस्थान (21,317), मध्य प्रदेश (19,508), महाराष्ट्र (16,614), और आंध्र प्रदेश (13, 455)।

पीएम श्री बारे में

पात्रता

- सभी प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-5 या 1-8)।
- माध्यमिक (कक्षा 1-10 या 6-10)।
- वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1-12 या 6-12)।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- मंत्रिमंडल ने 7 सितंबर 2022 को PM SHRI नामक एक नई केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी।
- योजना के तहत, केंद्र सरकार, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से 14,597 मौजूदा स्कूलों का चयन किया जाएगा।
- केंद्र की इस योजना से 18 लाख छात्रों को सीधे लाभ होने की उम्मीद है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- एनईपी 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्कूलों को मॉडल संस्थानों या पीएम श्री स्कूलों के रूप में पुनर्विकास किया जाएगा।
- ये स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करेंगे तथा छात्रों को 21वीं सदी के प्रमुख कौशलो से युक्त करने का प्रयास करेंगे।
- ये स्कूल लैब, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, खेल उपकरण, आर्ट रूम आदि सहित आधुनिक बुनियादी ढांचे से युक्त होंगे।
- इन्हें जल संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, ऊर्जा कुशल बुनियादी ढाँचे और पाठ्यक्रम में जैविक जीवन शैली के एकीकरण के साथ हरित विद्यालयों के रूप में भी विकसित किया जाएगा।

· वित्त पोषण और कार्यान्वयन

- 2022-23 से 2026-27 तक पाँच वर्षों के लिए इसे कुल ₹27,360 करोड़, की परियोजना लागत के साथ लागू किया जाएगा जिसमें ₹18,128 करोड़ का योगदान केंद्र सरकार देगी।
- 0 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश "एनईपी के पूर्ण अनुपालन " पर सहमति जताते हुए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे।
- 0 उन्हें या तो केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए और उनके पास UDISE+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन पुस) कोड लागू हो सकता है।

· स्कूल चयन प्रक्रिया

- न्यूनतम बेंचमार्क (यूडीआईएसई+ डेटा के विश्लेषण द्वारा) को पूरा करने वाले स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- अंतिम चरण प्रतोयोगिता पर आधारित होगा।
- राज्यों, केंद्रीय विद्यालयों या जवाहर नवोदय विद्यालयों की टीमें दावों का निरीक्षण और सत्यापन करने के लिए आवेदक संस्थान का दौरा करेंगी।
- इसके बाद वे शिक्षा मंत्रालय को चयनित स्कूलों की सिफारिश करेंगे।
- मंत्रालय एक ब्लॉक या शहरी स्थानीय निकाय से अधिकतम दो स्कूलों का चयन करेगा - एक प्राथमिक और दूसरा या तो माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक।

यूडीआईएसई

- यह एक ऐसा मंच है जो एक ऑनलाइन डेटा संग्रह फॉर्म के माध्यम से एक स्कूल की प्रोफ़ाइल, भौतिक बुनियादी ढांचे, शिक्षकों, नामांकन, परिणाम आदि के बारे में जानकारी एकत्र करता है जिसमें कई प्रदर्शन संकेतकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

संक्षिप्त सुर्खियां

वायरोवोर

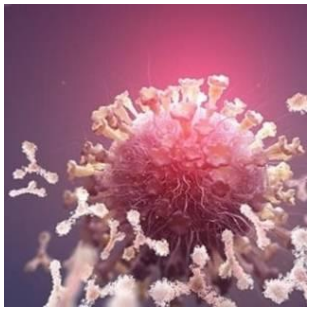

प्रसंग

हाल ही में, शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने प्रथम ज्ञात " वायरोवोर र" (एक वायरसग्राही जीव) की खोज की है।

मुख्य विशेषताएं:

- वैज्ञानिकों ने पाया कि हालटेरिया की एक प्रजाति - जो सूक्ष्म पक्ष्माभी हैं तथा सम्पूर्ण विश्व के मीठे पानी में पाया जाता है , - बड़ी संख्या में संक्रामक क्लोरोवायरस का भक्षण कर सकता है।
- दोनों एक जलीय आवास साझा करते हैं।

वायरोवोर के बारे में

- वायरोवोर एक जीव है जो वायरस के सेवन से ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करता है।
- शब्द तकनीकी रूप से उन जीवों को संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से या पूरी तरह से वायरस का उपभोग करते हैं परन्तु वर्तमान में इस श्रेणी में मात्र ऐसे जीव शामिल हैं जो किसी अन्य खाद्यपदार्थ की अनुपस्थिति में वायरस

	के उपभोग से प्राथमिक पोषण लाभ प्राप्त करते हैं। • वायरोवोर जीव हाल ही में खोजी गई एक प्रजाति है जिस पर एक जीवित जीव अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए निर्भर करता है। । • इसकी पहचान प्रोटिस्ट की एक वास्तविक प्रजाति के रूप में की गई है जो वायरस का भक्षण करती है। • प्रोटिस्ट की ये वायरसभक्षी प्रजातियों को अब अब विरोवोर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। • वे न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से बने होते हैं।
गंगासागर मेला 	**सन्दर्भ** हाल ही में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 'गंगासागर मेले' के लिए 'राष्ट्रीय दर्जा' की मांग की। **मुख्य विशेषताएं :** • गंगासागर मेला प्रतिवर्ष राज्य के 24 दक्षिण परगना में गंगासागर द्वीप पर आयोजित होता है। • गंगासागर मेले के दौरान देश भर से श्रद्धालु मकर संक्रांति (मध्य जनवरी) के दौरान पवित्र गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। • गंगासागर द्वीप कोलकाता के दक्षिण में लगभग 100 किलोमीटर (54 समुद्री मील) बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित गंगा डेल्टा में है। • कहा जाता है कि यह मेला कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ-सम्मेलन है
हिमाचल प्रदेश में सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना 	**सन्दर्भ :-** हाल ही में, सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2,614.51 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी। **मुख्य विशेषताएं:** • क्षमता- 382 मेगावाट। • स्थापना- सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। • स्थान- यह परियोजना शिमला और मंडी जिलों दोनों को कवर करते हुए सतलुज नदी पर बनेगी। इसके पांच साल में पूरा होने की उम्मीद है। • प्रकार- यह सतलुज नदी की जलविद्युत क्षमता का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन की गई नदी प्रकार की योजना है। **महत्व** ▪ यह स्थिरता के पहलू को मुख्या केंद्र के रूप में रखते हुए उद्योग, कृषि और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बिजली की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करेगा, । ▪ यह क्षेत्र के रोजगार और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अलावा देश के भीतर उद्यमिता के अवसरों को प्रोत्साहित करेगा।
नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल	**सन्दर्भ** हाल ही में, विभिन्न केंद्रीय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की मंजूरी के लिए राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर 75 हजार से अधिक स्वीकृतियां दी गई हैं। **मुख्य विशेषताएं:**

- NSWS पोर्टल 2021 में लॉन्च किया गया था।
- यह वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य निवेशकों को देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक विभिन्न पूर्व-संचालन अनुमोदनों के लिए आवेदन करने की अनुमति देना है।
- वर्तमान में, निवेशक पोर्टल पर 27 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 19 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- यह पोर्टल सिस्टम में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही लाने में मदद करेगा।
- समस्त सूचनाएं एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी।
- यह मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएलआई योजना आदि जैसी अन्य योजनाओं को भी मजबूती प्रदान करेगा।

ग्राम रक्षा समितियां

प्रसंग

हाल ही में, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनके लिए डोडा जिले की तरह एक ग्राम रक्षा समिति (वीडीसी) गठित की जाएगी।

ग्राम रक्षा समिति (वीडीसी)

- वीडीसी का गठन पहली बार तत्कालीन डोडा जिले (अब किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिले) में 1990 के दशक के मध्य में उग्रवादी हमलों के विरुद्ध बल गुणक के रूप में किया गया था।
- तत्कालीन जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दूरस्थ पहाड़ी गांवों के निवासियों को हथियार प्रदान करने और उन्हें अपनी रक्षा के लिए हथियारों का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया।
- वीडीसी का नाम बदलकर अब विलेज डिफेंस गार्ड्स (वीडीजी) कर दिया गया है।
- जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्रों में वीडीजी स्थापित करने की नई योजना को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल मार्च में मंजूरी दी थी।
- वीडीसी सदस्य की तरह, प्रत्येक वीडीजी को एक बंदूक और 100 राउंड गोलियां प्रदान की जाएँगी।
- वीडीजी संबंधित जिले के एसपी/एसएसपी के निर्देशन में काम करेंगे।

एफएसएसएआई द्वारा ईट राइट स्टेशन

प्रसंग

भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता, पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5-स्टार 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन से सम्मानित किया गया है।

मुख्य विशेषताएं:

- FSSAI द्वारा यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने वाले रेलवे स्टेशनों को 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन प्रदान किया जाता है।
- 5-स्टार रेटिंग यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्टेशन द्वारा पूर्ण अनुपालन का संकेत देती है।
- स्टेशन को 1 से 5 की रेटिंग के साथ FSSAI-अनुसूचित तृतीय-पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है।
- यह प्रमाणन 'ईट राइट इंडिया' आंदोलन, FSSAI द्वारा सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रयास, का भाग है-।

- ईट राइट इंडिया भोजन को पीपल एंड प्लेनेट दोनों के लिए उपयुक्त सुनिश्चित करने के लिए विनियामक, क्षमता निर्माण, सहयोगात्मक और सशक्तिकरण दृष्टिकोणों का विवेकपूर्ण मिश्रण अपनाता है।

नए इलेक्ट्रोलाइट की खोज :अमोनिया संश्लेषण हो सकता है सहायक

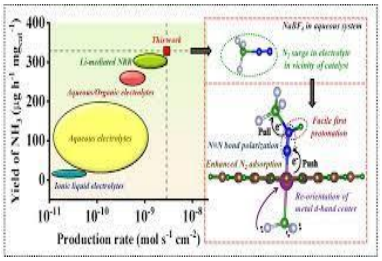

संदर्भ

एक नया जलीय इलेक्ट्रोलाइट की खोज की गई है यह संभवतः इलेक्ट्रोकेमिकल अमोनिया संश्लेषण को अधिक कुशल बनाने में मदद कर सकता है। इस प्रकार यह हरित ऊर्जा या हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिए उपयोगी होगा।

मुख्य विशेषताएं:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएनएसटी) मोहाली के वैज्ञानिकों ने (एनएबीएफ4) नामक एक नया इलेक्ट्रोलाइट प्रस्तुत किया है।
- यह न केवल माध्यम में एक N2-वाहक के रूप में कार्य करता है, बल्कि अमोनिया (NH3) के उच्च उत्पादन हेतु सक्रिय सामग्री संक्रमण धातु-डोप्ड गैर कार्बन (MnN4) के साथ एक पूर्ण "सह-उत्प्रेरक" के रूप में भी काम करता है।
- इस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा NH3 की उच्च उत्पादन दर औद्योगिक पैमाने पर पहुंच गई और किसी अन्य इलेक्ट्रोलाइट माध्यम में लगभग सभी मानक उत्प्रेरकों को पार कर गई है।
- ध्यातव्य है कि NH3 के स्रोत का अच्छी तरह से अध्ययन किया गया था और मुख्य रूप से शुद्ध N2 गैस की विद्युत रासायनिक कमी (N2 को NH3 में परिवर्तित करने के लिए इसे N2 संतृप्त इलेक्ट्रोलाइट बनाकर) की पुष्टि की गई थी।
- जर्नल पीएनएएस में प्रकाशित यह शोध जलीय माध्यम में N2 की घुलनशीलता के बारे में लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने और परिवेश की स्थिति में एनआरआर द्वारा अमोनिया की औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन दर प्राप्त करने के लिए एक नया दृष्टिकोण है।
- इस काम के लिए एक पेटेंट दायर किया गया है और वैज्ञानिक अब औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया उत्पादन की तीव्र दर के लिए इलेक्ट्रोलाइजर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

आरुद्र दर्शन

प्रसंग

कुड्डालोर और पड़ोसी जिलों के हजारों भक्तों ने अरुद्र दर्शन उत्सव के दौरान , चिदंबरम में श्री नटराजर मंदिर के रूप में लोकप्रिय श्री सबनयगर मंदिर के जुलूस को देखा।

मुख्य विशेषताएं:

- यह अनिवार्य रूप से एक शैव उत्सव है और भगवान शिव के लौकिक नृत्य मनाया जाता है। इस लौकिक नृत्य को नटराज रूप द्वारा दर्शाया जाता है।
- आरुद्र दर्शन भगवान शिव से जुड़े प्रमुख दिवसों में से एक है। यह
- शिव के लौकिक नृत्य को समर्पित है।
- अरुद्रा सुनहरी लाल ज्वाला का प्रतीक है और भगवन शिव इस लाल ज्वाला वाली ज्योति के रूप में नृत्य करते हैं।
- भगवान शिव का लौकिक नृत्य पांच गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है - निर्माण, संरक्षण, विनाश, अवतार और निस्तारण।

	• संक्षेप में, यह निर्माण और विनाश के सतत चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह लौकिक नृत्य कण-कण में होता है तथा यह समस्त ऊर्जा का स्रोत है। अरुद्र दर्शन भगवान शिव के इस परमानंद नृत्य का जश्न मनाता है। • चिदंबरम नटराज मंदिर में आरुद्र दर्शन का बहुत महत्व है और यह मरगज़ी ब्रह्मोत्सवम के समापन का प्रतीक है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	**सन्दर्भ :-** एनसीपीसीआर ने हल्द्वानी विरोध प्रदर्शन में नाबालिगों के कथित उपयोग पर नोटिस जारी किया। इसमें उल्लेख किया गया है कि कम उम्र के बच्चों को इन प्रतिकूल मौसम स्थितियों में विरोध स्थल पर लाया गया है जो उनके स्वास्थ्य और भलाई के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। **एनसीपीसीआर के बारे में:** • राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी। • आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक प्रणालियां भारत के संविधान के साथ-साथ बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में वर्णित बाल अधिकारों की दृष्टि के अनुरूप हों। • आयोग ने एक बच्चे की परिभाषा को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले व्यक्ति के रूप में की है। • आयोग एक अधिकार-आधारित परिप्रेक्ष्य की परिकल्पना करता है, जो राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर परिभाषित प्रतिक्रियाओं सहित प्रत्येक क्षेत्र की विशेषताओं और ताकत को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में प्रवाहित होता है, । • · आयोग बच्चों और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य के लिए एक अनिवार्य भूमिका की परिकल्पना करता है।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare